>

Title: Situation arising due to crop holiday declared by farmers in Konaseema area of East Godavari and Eight other districts in Andhra Pradesh.

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक ऐसी गंभीर समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या केवल कृषि जगत के लिए ही एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी नहीं होगी, बल्कि मैं मानता हूं कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी।

दो दिन पहले मैं आंध्र प्रदेश गया था और विशेष रूप से ईस्ट गोदावरी जिले में गया था। आंध्र प्रदेश के आठ-नौ जिले ऐसे हैं जहां के किसानों को फसल की उचित कीमत न मिलने के कारण उन्होंने यह फैसला किया है कि इस साल वे अपनी पैडी की बुवाई नहीं करेंगे यानी क्रॉप-होलीडे की घोषणा कर दी है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार क्रॉप-होलीडे यानी हड़ताल करने की घोषणा आंध्र के किसानों ने की है। इसी प्रकार का असंतोष लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण देश के सारे किसानों में पैदा होता जा रहा है। मैं सारे जिलों का उल्लेख करना नहीं चाहूंगा, वैसे 8-9 जिले इस प्रकार के हैं जिन्हें अपनी इनपुट कॉस्ट नहीं मिल पा रही है। संसद में भी बार-बार आग्रह किया गया है कि फारमर्स-कमीशन ने, डा. स्वामीनाथन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कई वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी है लेकिन आज तक उसकी रिक्मेंडेशन्स को लागू नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि डा. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को यह सरकार जितनी जल्दी लागू कर देगी, उतनी जल्दी इस देश के किसानों का कल्याण हो जाएगा। मनरेगा के कारण भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में जो स्किल्ड लेबर होता है, जिसमें काम करने की कुशलता होती है, उसका संकट पैदा होता जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, मैं मनरेगा को समाप्त करने की मांग नहीं कर रहा हूं। जिन किसानों ने क्रॉप-होलीडे की घोषणा की है और इस साल फसल नहीं बोई है, उन्हें कम से कम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ का कम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। केवल वही के किसानों में नहीं, बल्कि देश के समस्त किसानों के समक्ष ऐसा संकट पैदा हुआ है। इनपुट कॉस्ट न मिलने के कारण, मैं संसद में यह मांग करता हूं कि एक स्टुमिलेटेड पैकेज, स्पेशली डिजाइन्जड पैकेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देश के किसानों को दिया जाना चाहिए। इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और सबसे बड़ा पेशा कृषि है। इसलिए मैं संसद में यह भी मांग करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को एक नेशनल ऑकुपेशन, एक राष्ट्रीय पेशा घोषित किया जाना चाहिए और किसानों और कृषि जगत की समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आज बुलाए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तभी हम कृषि जगत की समस्याओं से जूझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया :

श्री शैलेन्द्र कुमार,

श्री शिवकुमार उदासी,

डा. भोलासिंह,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्रीमती दर्शना जरदोश,

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट,

सुश्री जे. शांता,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

श्री चन्दूलाल साहू,

श्री जीतेन्द्र सिंह बुन्देला,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्री अशोक अर्गल,

श्री गणेश सिंह,

श्री गजानन ध. बाबर,

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर,

श्रीमती मीना सिंह,

श्री प्रबोध पांडा,

श्री जगदानन्द सिंह,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री शिवराम गौडा,

श्री राकेश सचान,

श्री एम.बी.राजेश,

श्री कीर्ति आजाद,

श्रीमती विजया चक्रवर्ती,

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया,

श्री के.डी. देशमुख,

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन,

श्री मोहन जेना,

श्री गोरखनाथ पाण्डेय,

श्री दारा सिंह चौहान,

श्री सिद्धांत महापात्र,

श्री प्रेम दास राय,

श्रीमती संतोष चौधरी,

डा. राजन सुशांत,

श्री नारनभाई काछड़िया,

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण,

श्रीमती पुतुल कुमारी,

श्री लक्ष्मण टुडु,

श्री विश्व मोहन कुमार,

श्री राकेश सिंह,

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी,

श्री तथागत सत्पथी,

श्री हरिभाउ जावले,

श्री सुशील कुमार सिंह,

श्री राजू शेट्टी, को माननीय राजनाथ सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

Shri Pulin Bihari Baske – not present.